

‘अप्प दीपो भव’ वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18

WPP Licence No.- U(C)-101/2016

R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.06.2016

Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रुपये

प्रेषक : डॉ० उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्राव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com

E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 19 ● अंक 14 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 जून, 2016

अन्तर्राष्ट्रीय त्रिदिवसीय बौद्ध धम्म महासम्मेलन सम्पन्न

समता, बन्धुता एवं संघर्ष के बिना आरक्षण बचाना मुश्किल

दुःखों से मुक्ति का मार्ग है ‘बौद्ध धर्म’ : डॉ. उदित राज

हरदोई, (उत्तर प्रदेश) में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 मई 2016 को प्रातः 8:30 बजे बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित ‘दि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया’ (भारतीय बौद्ध महासभा) की जनपद ईकाई हरदोई (30प्र०) के जिलाध्यक्ष श्री लाल बिहारी बौद्ध के नेतृत्व में बुद्ध पूर्णिमा महाधम्म यात्रा जी.आई.जी मैदान हरदोई से जनपद के पिहानी, शशाहाबाद, पाली, रूपापुर, हरपालपुर, सांडी, बिलग्राम होते हुए लगभग 200 कि.मी. की यात्रा 143 चार पहिया वाहनों, 2-डी.जे. के साथ 3-झांकियों, जिसमें क्रमशः भगवान बुद्ध, डॉ० अम्बेडकर एवं पेरियर ललई सिंह यादव के चित्र लगे थे।

सायकल लगभग 5.00 बजे पुनः जी.आई.सी. मैदान हरदोई मुख्यालय से हाथियों, झांकियों, बैण्ड बाजों के साथ, नुमाइश चौराहा, सिनेमा चौराहा होते हुए पुनः गांधी मैदान पहुंचा। रात्रि में ‘गीतों भरी शाम-बुद्ध के नाम’ का मंचन भगवान वत्स भारती द्वारा संगीतमय प्रस्तुति रात्रि 2.00 बजे तक जारी रही तथा कार्यक्रम का संचालन श्री लाल बिहारी बौद्ध ने किया।

22 मई 2016 को प्रातः 8 बजे बुद्ध



वन्दना तथा 9 बजे थाईलैण्ड के भन्ते सुधम्म नाथो द्वारा धम्म देशना 10 बजे तक तत्पश्चात ई० अनिल कुमार, कस्टम कमिश्नर श्री के.के. कठेरिया, श्री प्रेम प्रकाश-पुलिस महानिरीक्षक, सीतापुर (30प्र०) तथा हाईकोर्ट की लखनऊ बेन्च के पूर्व न्यायमूर्ति श्री खेमकरन लाल साहब, तथा वराणसी (30प्र०) के आर.टी.ओ श्री पी.सी. सत्यार्थी का व्याख्यान हो रहा था, इसी बीच महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य तथा ‘दि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया’ के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय रामदास अठावले का आगमन भगवान बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहब अमर रहें के गगन भेदी नारों के साथ हुआ और उनका स्वागत ही चल रहा था कि उत्तर-पश्चिम, दिल्ली से लो कसभा सदस्य, ‘अनुसूचित जाति-जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ एवं लार्ड बुद्धा क्लब’ के

राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. उदित राज का भी आगमन हुआ तथा उनका भी स्वागत भगवान बुद्ध की करुणा हों- करुणा हो, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें- अमर रहें के गगन भेदी नारों से हुआ, उनके साथ ‘दि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया’ के प्रदेश अध्यक्ष, श्री जगजीवन प्रसाद जो डॉ. उदित राज के नेतृत्व में गठित ‘अनु. जाति-जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ’ के राष्ट्रीय समन्वयक एवं 30प्र० के अध्यक्ष तथा इन दोनों संगठनों के अन्य पदाधिकारी सर्वश्री बी.डी. भारती, के.पी. चौधरी सहित मानव कल्याण सेवा धर्म के संस्थापक श्री मोहम्मद इकबाल जी भी थे।

ज्ञातव्य हो कि डॉ. उदित राज जी ने राजनीति में जाने का बिगुल, हरदोई से ही बजाया था और उनके द्वारा दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय महा रैलियों

शेष पृष्ठ 2 पर....

जन-जन तक व्यक्तिगत तौर से या संगठनात्मक तौर से संदेश न तो पहुंचाया जा सकता है और न ही समाचार और समस्याओं से परिसंघ का कार्यालय और राष्ट्रीय चेयरमैन अवगत हो सकते हैं। समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है और अब आप भी बदलो। नहीं बदलो तो मिशन और प्रयास दोनों अधूरा रह जाएगा। अब सस्ती, सुगम, तकनीक उपलब्ध है तो उसे इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें।

बार-बार आपको कहा जा चुका है कि मिशनरी साधियों के नाम, नम्बर और ईमेल भेजें। इसके प्रभावशाली नतीजे नहीं आए लेकिन थोड़ा-बहुत भी अपनी जिम्मेदारी और दर्द महसूस करेंगे तो अब से इस प्रक्रिया को तेज कर दें।

बिना आर्थिक सहयोग के आंदोलन नहीं चलते। हम कर्मचारी-अधिकारी बने तो क्या बिना आरक्षण के। आरक्षण का अधिकार हमारे मां-बाप ने नहीं दिया और न ही अध्ययनरत रहते हुए हमने इसके लिए लड़ा। यह अधिकार बाबा साहेब ने दिया जिसका हम उपभोग कर रहे हैं। हम लोगों में से कुछ घमंडी, कुतर्की, जातिवादी, कह सकते हैं कि परिश्रम से पढ़ाई किया तब जाकर अधिकारी-कर्मचारी बने हैं। इनसे पूछा जाए कि दादा-परदादा क्यों नहीं पढ़-लिखकर अधिकारी-कर्मचारी बने? यह एक अवसर है, जिसकी वजह से यह सब संभव हुआ। जो अपने को परिश्रमी और दिमागदार होने की बात करते हैं, वह ठीक है, लेकिन यह अपने स्वार्थ में किया गया है, इससे समाज का क्या लेना-देना? अतः जो धन और सम्मान कमा रहे हैं वह बाबा साहब, अवसर और समाज में जन्म लेने के कारण है। समाज का अधिकार है इस कमाई और सम्मान के बंटवारे का। पदोन्नति और निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई आसान नहीं है, इसलिए आर्थिक सहयोग के लिए परिसंघ का खाता संख्या दिया जा रहा है, उसमें सहयोग राशि जमा करके व्हाट्सअप या ईमेल के द्वारा सूचित करें।

Account details :

Name of Beneficiary :

All India Confederation of SC/ST Organisations

Name of Bank : State Bank of India

Saving Bank Ac No.:30899921752

Branch Name :

Chanderlok Building, 1st Floor, Janpath, New Delhi

IFSC Code : SBIN0001639

संपर्क और जुड़ने के लिए



parisnagh1997@gmail.com



97-17-046-047



Facebook www.facebook.com/
parisangh.all.india.uditraj

सुमित कुमार 09868978306

आज के दौर में भगवान बुद्ध की उपयोगिता

21 मई को बुद्ध पूर्णिमा पड़ रही है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। धर्म की बात हो और उसमें महिला और पुरुष का विमर्श कैसे न हो। बड़े धर्मों से लेकर छोटे धर्म तक ने पुरुष को महत्व दिया है। क्यों नहीं कोई महिला किसी धर्म का प्रवर्तक या आविष्कारक हुई ? इससे भी पता चलता है की हजारों वर्षों से समाज पुरुषवादी रहा है। जब भगवान गौतम बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किया तो उस समय का समाज पुरुष सत्तावादी था। बौद्ध धर्म में खुद के कर्म से पाप और पुण्य निर्धारित होता है न कि चली आ रही परम्पराओं या कोई अन्य कारणों से। महिलाओं के उत्थान में जितना बौद्ध धर्म का योगदान है शायद ही किसी और धर्म-पंथ में हो ?

आज से पच्चीस सौ वर्ष पहले यह मान्यता थी की बिना पुत्र के मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक कर्म-कांड, पिंडदान इत्यादि पुत्र ही कर सकता था। महिला का कार्य बच्चा पैदा करना और घर संभालना हुआ करता था और लगातार व्यस्त रखने के लिए घरेलू काम की जिम्मेदारियां दी जाती थी। यह मानते हुए कि अगर यह न किया गया तो खाली दिमाग कुछ खुराफाती काम कर सकता है। पति की

सेवा करना उसका परम कर्तव्य था। नारी खुद मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी उसके लिए उसका दूसरा जन्म पुरुष के रूप में होना जरूरी था। जैसे कि अभी भी कहीं-कहीं पर महिला को अपवित्र समझा जाता है, उस समय के हालात तो बड़े भयावह थे। पुत्र का जन्म देना जरूरी था क्योंकि धार्मिक क्रिया कलाप और वंश चलाना तभी संभव था। गौतम बुद्ध इससे बहुत क्षुब्ध हुए और चुनौती दिया कि कैसे महिला पुरुष के पाप-पुण्य एवं बुरा-भला के लिए जिम्मेदार हो सकती है ? इस तर्क से महिला समाज को बड़ी राहत मिली वरना तमाम सारे दुखों और पापों का कारण उन्हें ही समझा जाता था।

बुद्ध के धम्म प्रचार से लड़कियों और महिलाओं को अपना स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मिला। वे माँ-बाप भाई-बहन की परवरिश खुद कर सकती थी और संपत्ति रखने का अधिकार भी। अपने सास-ससुर का ध्यान उसी तरीके से रखना चाहिए जैसे अपने स्वयं माँ-बाप का। परिस्थिति काल के अनुसार यह उचित माना गया कि वह घर को संभाले। एक समय की बात है जब कौशल के राजा को पुत्री की प्राप्ति हुई तो वह अप्रसन्न हुए।

उनको गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया कि कुछ महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बुद्धिमान हैं तथा इनमें प्रेम-स्नेह और करुणा कहीं ज्यादा होती है। बुद्ध ने उपदेश दिया कि विवाहित महिला को अपने पति के साथ बर्ताव सही रखना चाहिए। निरंकुशता से दूर और फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। पति की संपत्ति का ध्यान रखना और व्यभिचार से बचना, स्वभाव नम्र हो और काम काज में निपुणता। उसी तरीके से पुरुष के लिए भी उन्होंने पार्मिताएँ बताईं।

भगवान बुद्ध सुंदरता के ऊपर विचार व्यक्त करते हैं। खेमा नाम की सुंदरी राजा बिंबसार के दरबार की रौनक थी और वह अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड करती थी। एक दिन वहाँ जा पहुंची जहाँ बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। बुद्ध को मनोविज्ञान में महारथ हासिल थी और वह समझ गए और उन्होंने प्रवचन दिया कि बचपन से जवानी और एक दिन बुढ़ापा सबका आना है। जब बुढ़ापा आता है तो सहारे से चलना होता है, दाँत आदि टूट जाते हैं और शरीर भी साथ नहीं देता है। खेमा पर इसका घहरा असर पड़ा और अंत में उसका घमंड टूट और बाद में जाकर बहुत बड़ी बुद्ध प्रचारक बनी। कीसा गौतमी कि चर्चाएँ तो आम हैं। कीसा

गौतमी को बड़ी मुश्किल से संतान की प्राप्ति हुई थी। परिवार बड़ा था और वही एक संतान थी जिसकी असामयिक मृत्यु हुई। रोते-रोते बेहाल हो गयी तो लोगों ने कहा कि बुद्ध में शक्ति है कि मरे को जिंदा कर देते हैं। कीसा गौतमी उनके पास पहुँचती है और विलाप करते हुए कहती है कि उसके बच्चे को जिंदा करें। बुद्ध कहते हैं कि जाकर के ऐसे घर से सरसों का दाना लाओ जहां मृत्यु न हुई हो तो बच्चा पुनः जीवित हो सकता है। वह जाती है और ऐसा घर नहीं मिलता है, जहां पर कभी मृत्यु न हुई हो। इससे उसे समझ में आ जाती है कि मृत्यु निश्चित है। इसी तरह से दूसरी घटना घटित होती है कि पटवारा नाम कि महिला के घर सभी मर जाते हैं और वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगती है। उसे भी उपदेश देते हुए भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि माँ-बाप, भाई-बहन या और कोई मृत्यु से बचा नहीं सकते। उपदेश इसे भी समझ आता है और अंत में आगे चल करके बड़ी भिक्षुणी बनती है।

बुद्ध के धम्म प्रचार के पाँच साल के अंदर भिक्षुणी संघ कि स्थापना होती है जिसको बहुत बड़ी सफलता मिली। जिस तरह से भिक्षुओं को प्रचार

प्रसार करने की आजादी थी वैसे ही भिक्षुणियों को मिली। न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी प्रचारक बन कर देश-विदेश में धम्म प्रचार का कार्य किया। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा प्रचार करने श्रीलंका गयी और इस तरह से कई शताब्दियों तक भिक्षुणी संघ सफल कार्य करता रहा। अंत में पुरुष समाज ने येन-केन प्रकारेण अपना कब्जा जमा लिया और भिक्षुणी संघ कमजोर हो गया। चीन और जापान में उस समय की भिक्षुणी परंपरा को आज भी देखा जा सकता है और वहाँ पर अभी भी महिला संघ आत्म निर्भर होकर धम्म का काम कर रहा है। धर्म अपने साथ संस्कार और सोच भी देता है और यही कारण है कि बर्मा, थाइलैंड, कंबोडिया, चीन, जापान आदि देशों में जहां पर बौद्ध धर्म है वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी शिक्षा, कारोबार आदि क्षेत्र में अधिक है। बौद्ध धर्म में तर्क को स्थान दिया जाता है और इंसान के स्वयं के कर्म से ही उसका बुरा-भला निश्चित होता है। ऐसे में महिला न अपवित्र है न किसी पाप की वजह है। इस विचार से स्वाभाविक रूप से महिला-पुरुष समान हो जाते हैं।

- डॉ. उदित राज



पृष्ठ 1 का शेष.....

में तथा वर्ष 2001 में दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 10 लाख लोगों द्वारा एवं साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा के कार्यक्रम में हरदोई से लगभग 4-5 हजार लोग दिल्ली गये थे।

दोनों प्रमुख अतिथियों के स्वागत के बाद पहले मा० रामदास अठवले साहब को मंच से सम्बोधित करने के लिए बुलाया गया, माननीय अठवले साहब ने कहा कि वे हरदोई में बाबा साहब के कारवां को महाराष्ट्र से आगे बढ़ाने आये हैं। तथागत बुद्ध की करुणा मैत्री का संदेश भारत से कम्बोडिया, जापान, बर्मा, थाईलैण्ड, श्रीलंका, आदि देशों में पहुंचा भारत में पुनर्जागरण का कार्य बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया। भारत को बौद्धमय भारत बनाने की आवश्यकता है। मा० अठवले जी ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ पार्टी के उ०प्र० अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी, प्रदेश प्रभारी-डॉ० आर. आर. मौर्या एवं राष्ट्रीय सचिव एड. राजाबक्श वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जी.पी. गुप्ता प्रदेश सचिव व श्री बालेश्वर सिंह जिलाध्यक्ष, प्रतापगढ़ ई. सियाराम वर्मा, जिलाध्यक्ष लखनऊ, हरदोई जनपद के अध्यक्ष श्री हरनाम सिंह आदि माननीय अठवले जी के साथ थे। माननीय अठवले जी के सम्बोधन के बाद उनको ‘दि बुद्धिष्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया’ के प्रदेश अध्यक्ष जगजीवन प्रसाद तथा जिलाध्यक्ष श्री लाल बिहारी सहित तमाम पदाधिकारियों ने स्मृति चिह्न एवं पंचशील का पट्टा पहिनाकर सम्मानित किया। माननीय अठवले साहब ने उपस्थिति भिक्षु संघ को दान देने के लिए 10,000 रुपये भेजने की घोषणा की।

माननीय रामदास अठवले के सम्बोधन के बाद उत्तर-पश्चिम दिल्ली से लोकसभा सदस्य चुने गये डॉ. उदित राज को सम्बोधित करने के लिए उन्हें मंच पर आमंत्रित किया गया सबसे पहले उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। मा० डॉ. उदित राज ने अपने सम्बोधन में उपस्थिति पूज्य भिक्षु संघ को मुखातिब होकर उन्हें नमन किया और

उपस्थिति जनसमूह एवं उनके साथ आये संगठन में सभी पदाधिकारियों का भी नाम लिया उन्होंने हरदोई को अपनी कर्म-भूमि बताते हुए श्री के.पी राहुल, आर. के राज, शिव शंकर, लाल बिहारी, अमित राज आदि सभी का नाम लेकर अपना सम्बोधन शुरू किया। उन्होंने श्री लाल बिहारी की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उन्हें इस अन्तरराष्ट्रीय बौद्ध धम्म महा सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर आये दिन लोग मा० रामविलास पासवान, मा० रामदास अठवले एवं डॉ. उदित राज का एक साथ फोटो बनाकर पता नहीं क्या-क्या लिखते रहते हैं, जबकि इन्हीं तीनों सांसद समाज को जगाते रहते हैं। शेष सैकड़ों दलित सांसदों का कोई नाम भी नहीं लेता जबकि संसद में अकेले जितने सवाल आपकी सुविधाओं एवं आरक्षण के बारे में करता हूँ शायद ही सभी दलित सांसद मिलकर नहीं करते आप लोग सोशल मीडिया एवं इन्टरनेट से जानकारी कर सकते हैं।

डॉ. उदित राज ने जैसे ही उ०प्र० सरकार में कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने की बात कही, भीड़ से आवाज आई कि धर्म के आयोजन में आरक्षण की बात न की जाए, फिर क्या था डॉ. उदित राज जी ने कहा कि बाबा साहब ने सबसे पहले हम-आपको आरक्षण दिलाया था, धर्म की बात बाद में कहीं थी हम उनसे अलग नहीं हैं। यदि आज आरक्षण न मिला होता तो आज लाल बिहारी यहां अन्तरराष्ट्रीय स्तर का बौद्ध धर्म महाअधिवेशन करने की हिम्मत न जुटा पाते और यदि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर न बन पाता तो यहां आपको सम्बोधित करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। आरक्षण और धर्म का कार्य साथ-साथ चलना चाहिए। आज हमारे बीच कुछ भिक्षु भी जाति की बात करते रहते हैं जबकि जाति का उन्मूलन कर बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने की

बात कही थी। उन्होंने आगे बताया कि मैं सांसद बाद में बना हूँ, नौकरी में रहते हुए हमने अनुसूचित जाति-जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के माध्यम से आरक्षण बचाओ आन्दोलन चलाकर संविधान में तीन संशोधन 81,82 एवं 85 वां संविधान संशोधन कर दलितों का आरक्षण बचाने का कार्य किया था। और समाज की निष्क्रियता एवं तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की आरक्षण के मुद्दे पर उदासीनता ने आज पदोन्नति में आरक्षण गवां दिया। फिर भी मैं संसद के अन्दर और बाहर पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने की मांग लगातार उठा रहा हूँ। आज भगवान बुद्ध की अत्त दीपो भव के संदेश अपनाकर दुःख है तो उसका कारण है और कारण है तो निवारण है के सिद्धान्त पर ही व्यक्ति-समाज व राष्ट्र का नवनिर्माण संभव है। उन्होंने कहा दुःखों से मुक्ति का मार्ग भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म है। उन्होंने तथागत बुद्ध के मैत्री एवं करुणा का संदेश का क्या मतलब है हम जब तक जातियों में बंटकर रहेंगे तो आरक्षण बच नहीं सकता। हमें जाटव आन्दोलन से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समता के लिए संघर्ष जरूरी है और बिना एकता एवं संघर्ष के आरक्षण नहीं बचेगा। अन्त में डॉ. उदित राज जी ने उपस्थित भिक्षु संघ को दान स्वरूप 10,000 रुपये नकद दिया और उपस्थिति जनसमूह को भिक्षुओं को दान देने की आदत डालनी चाहिए तथा बौद्ध भिक्षु निश्चिन्त होकर धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। डॉ. उदित राज जी को भी आयोजकों ने स्मृति चिह्न देकर सम्मान किया और आरक्षण बचाओ की लड़ाई में उनको मजबूती से सहयोग करने का वचन दिया।

23 मई प्रातः 8 बजे बुद्ध वन्दना भिक्षु संघ द्वारा तथा भन्ते महानाम दिल्ली द्वारा धम्म देशना तत्पश्चात 10 बजे शान्ति मार्च पूज्य भिक्षुओं द्वारा भारत के अमर शहीद रोहित वेमुला के नाम जी.आई.सी. मैदान तक जिलाभ्रमण कर श्रद्धांजलि सभा हुई और बाद में राहुल नागपाल एवं शशिभूषण द्वारा

संगीतमय प्रस्तुति पूर्वान्ह 11 बजे तक और अन्त में 410 बौद्ध भिक्षुओं को भोजनदान एवं चीवरदान के साथ दान की अन्य पारमिताओं को पूरा किया गया।

दोपहर 2 बजे 1000 गरीब महिलाओं को साड़ी दान तथा कार्यक्रम के अन्त में प्रमुख कार्यकर्ताओं व वालेन्टियर्स को सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह एवं पंचशील पट्टा आदि से सम्मानित किया गया, तीनों दिन लगभग 50 हजार लोगों को भोजन दान दिया गया।

अन्त में कार्यक्रम में विशेष सहयोग देने वाली संस्थाओं जैसे डॉ. अम्बेडकर स्टूडेन्ट, फ्रन्ट आफ इंडिया शाखा हरदोई, अम्बुजा जान कल्याण फाउन्डेशन, अम्बेडकर मेमोरियल संस्थान हरदोई, यूथ बुद्धिष्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, माया बिहारी इण्टर कॉलेज, आजाद भारत गैस,



कार्यक्रम में लाल बिहारी, जगजीवन प्रसाद सहित आयोजक ऊपर डॉ० उदित राज को एवं नीचे श्री रामदास आठवले को स्मृति-चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए



15 जून, 2016 को नवभारत टाइम्स में प्रकाशित लेख

शिक्षा व्यवस्था कहां फेल हुई

एक बहुत घातक प्रवृत्ति पैदा हो गयी है कि हर कमी के लिए राजनीतिज्ञ जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं, उसके बाद पुलिस और नौकरशाही। रंगभेद, घरेलू हिंसा, सिविल सोसाइटी के असंवैधानिक कृत्य आदि के लिए भी सबसे पहले राजनीति ही जिम्मेदार ठहराई जाती है। निर्भया कांड जब हुआ तो पूरा आक्रोश राजनीतिज्ञ और पुलिस पर व्यक्त हुआ। अफ्रीकी नागरिकों के ऊपर जो हाल में हमले हुए उसका एक कारण हमारे समाज की काले-गोरे की सोच की वजह भी रही है। लड़कियों और महिलाओं के प्रति पुरुष समाज की सोच हो या जाति के आधार पर भेदभाव अथवा काला-गोरा, इन सारी समस्याओं का समाधान मूलरूप से स्कूलों को करना चाहिए। शिक्षा का यह मतलब नहीं कि वह परीक्षा या प्रतिस्पर्धा पास करने के लिए ज्ञान से लैस करे बल्कि समाज के प्रति समझदारी भी विकसित हो। पिछले वर्ष अमेरिका के एक राज्य – नार्थ कैरोलिना जाना हुआ। वहां पर भारतीय डॉक्टरों का दबदबा है। एक डॉक्टर बहुत ही सफल हैं। जब उन लोगों से बात हो रही थी तो उनकी पत्नी ने शिकायत किया कि अमरीका में हमारे बच्चे संस्कार भूल गए हैं। जैसे ही यह सुना मेरी जिज्ञासा और गहराई में जाने की बन

गयी। पूछा कि क्या बात हो गयी? उन्होंने जवाब दिया कि स्कूल में पढ़ रहे उनके बच्चे किसी को भी दोस्त बना लेते हैं। कभी उनका काला दोस्त, कभी ट्रॉसजेंडर तो कभी किसी और मूल का। कहने व समझाने पर भी यहां बच्चे नहीं मानते और अपने मन की करते हैं। उस पर मुझे एहसास हुआ कि काश! अमेरिका जैसे स्कूल भारत में भी होते, जो केवल विषयों का ज्ञान ही नहीं देते बल्कि भेदभाव समाप्त करने की समझ भी। स्कूल और कॉलेज ही जीवन के वे पड़ाव हैं, जहां यह समझ विकसित होती है। धन्यवाद करना चाहिए कि वहां की ऐसी शिक्षा को कि मां-बाप चाहकर भी अपने बच्चे को रंगभेदी और जातिभेदी नहीं बना सकते। वहां के स्कूल की शिक्षा मां-बाप के प्रभाव से ज्यादा ताकतवर है। दिल्ली हो या देश का कोई और कोना अगर कोई गोरा मदद चाहे या रास्ता पूछे तो हम भारतीय अपने काम को शिथिल करते हुए भी मदद में जुट जाते हैं। यह भावना अफ्रीकी के साथ प्रायः नहीं होती। अगर अफ्रीकी रास्ते से गुजर रहा हो तो बहुत संभव है कि बच्चे ठेला मारें और काला व हल्की कहकर आवाज तो निकालते ही हैं। इस भेदभाव की मानसिकता को दूर न करने की जिम्मेदारी पूर्णतः शिक्षा

व्यवस्था पर थोपी जानी चाहिए। आखिर में दुनिया में हमारी इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन, लाखों अध्यापकों की क्या जिम्मेदारी है? सच्चाई को नकारना या झुठलाना एक नासूर के सिवा कुछ नहीं है। क्या इस सच्चाई को कोई नकार सकता है कि सांवली या काली लड़की की शादी मुश्किल से होती है। व्यावसायिक वर्ग में अक्सर यह देखा गया है कि भारी दहेज के साथ विवाह तय होता है। यह इतनी बड़ी सच्चाई है और नकार देना वैसा ही है, जैसे कि दिन को रात कहना। गांव में तो इसका वीभत्स रूप देखने को मिलता है कि ब्याह करके आई लड़की गोरी है या काली, इसकी चर्चा सबसे पहले होती है। अगर संयुक्त परिवार है और उसमें 3 या 4 बहू हैं और उसमें एक सांवली या काली हो तो सास से लेकर सभी उसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। रंगभेद की वजह से ऐसी बहू को ज्यादा काम करना पड़ता है और व्यवहार भी अधिक सहयोगात्मक और नम्र। गोरी बहू अक्सर इतराती है। कुछ ही सास या परिवार ऐसे हैं जो टीका-टिप्पणी किए बिना नहीं रह सकते कि बेचारी काली है तो क्या हुआ, काम-धंधे में आगे है। यह भी कहते हैं कि भले रंग-रूप में काली हो लेकिन दिल की साफ है। अगर लड़की पढ़ी-लिखी

है या उसके पास चुनाव करने की आज़ादी है तो वह भी गोरे लड़के को ही पसंद करती है। आर्थिक रूप से अगर निर्भर है तो समझ लो उसका व्यवहार लड़के जैसे ही होता है। भेदभाव न हो या तुष्टिकरण करना हो तो यह भी लोग कहते हैं कि चमड़ी भले सांवली हो तो क्या हुआ भगवान शंकर और कृष्ण भी तो सांवले थे। मां-बाप और समाज से तो इतनी उम्मीद की नहीं जा सकती कि वे अपनी आने वाली पीढ़ी को जातिभेद, रंगभेद, लिंग भेद से मुक्त करा सकें चूंकि वे भी उसी परंपरा से आते हैं। सामाजिक संस्था, राजनीति, सरकारी तंत्र की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे शिक्षित करें। शिक्षित करने की जिम्मेदारी तो केवल स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की ही होती है। इसके बाद पत्रकार, लेखक और कवि आदि की। सबसे ज्यादा विडंबना यह है कि इस समस्या का भी जिम्मेदार राजनीति और नौकरशाही पर मढ़ दिया जाता है। इससे राष्ट्र की दोहरी हानि हो रही है। पहला, पूरा शिक्षा तंत्र अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है और दूसरा निर्दोष राजनीति को भी इसके लिए कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। क्या शिक्षा व्यवस्था की सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि इम्तिहान में प्रश्न का उत्तर देने लायक बनाए।

अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति की नींव डाली वह उनकी सुविधानुसार थी। हैरानी तब होती है, जब आज़ाद भारत के लोग उन्हीं को दोष देते हैं, जबकि वे छोड़कर चले गए हैं। क्या अंग्रेजों ने अब भी रोका है कि हम अपने अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को न ढालें। अंग्रेजों ने तो तमाम सुधार लाए थे, जिसका विरोध हमारे रूढ़िवादी तत्वों ने किया था, चाहे वह सती प्रथा पर प्रतिबंध, बाल-विवाह या विधवा विवाह हो। अमेरिका ही नहीं ज्यादातर विकसित देश अगर आगे बढ़ें तो सबसे पहले शिक्षा में मूल्यों की वजह से। जापान में चाहे जितना अमीर घर का बच्चा हो, दोपहर में भोजन करने के बाद साफ-सफाई उन्हीं को करना होगा। इस माहौल में शिक्षित बच्चा क्या कभी घर की साफ-सफाई या गली-मोहल्ले की रखने में हिचकेगा। हमारे यहां उल्टा है कि अगर ज्यादा पढ़ ले और सरकारी नौकरी न ले सके तो समस्या ही समस्या है। न वह पुरतैनी पेशा कर सकता है और न ही शारीरिक श्रम। इसे करने में वह शर्म महसूस करता है। भारत बदल रहा है और यह बहुत अच्छा अवसर है कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करके रंग, लिंग व जाति भेदी सोच और पूर्वाग्रह को खत्म कर दिया जाए।

– डॉ० उदित राज

जुनून जब हावी होता है, सफलता मिल ही जाती है

किसने सोचा था कि बूंदी, राजस्थान जिले के ‘डाबी’ गांव का नाम रोशन करने वाली दलित समाज की बेटी ‘टीना डाबी’ सिविल सेवा परीक्षा 2015 में टॉप कर भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब होगी। किसे पता था कि डाबी के पिता श्री जसबंत सिंह ‘डाबी’ गांव से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली में आकर अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दिलाएं, पढ़ाई का बेहतर माहौल और साधन उपलब्ध कराएं, जिसके बल पर उनकी बेटी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप कर दुनिया में नाम रोशन करेगी। यह संभव हुआ, क्योंकि टीना ने अपने माता-पिता के संस्कारों के साथ-साथ बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के ‘शिक्षित बनों’ मूलमंत्र को अपना आदर्श मानते हुए इसे अपने जीवन में गंभीरता के साथ लागू किया और इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ती गयी। अंततः उन्हें इसमें ऐतिहासिक सफलता भी हासिल हुई, जिसकी चर्चा किए बिना कोई भी रह नहीं सकता। यह ऐतिहासिक परिणाम एक प्रकार से उनके जुनून को ही दर्शाता है। इसमें उसके माता-पिता के उचित मार्गदर्शन, सही एवं प्रभावशाली तथा बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के शिक्षा जैसे आधारभूत तत्व को अपनाने एवं उनके कहे हुए शब्दों को आत्मसात् करने पर ही संभव हो सका। हम टीना जी के साहस, त्याग, और लगन या कहे जुनून को सलाम करते हैं। भले ही उसकी जाति विशेष की पहचान उच्च जाति के लोगों को आसानी से नहीं हो पायी इसके चलते उन्हें जाति विशेष से हानि नहीं उठनी पड़ी हो लेकिन आगे आने वाले समय में उसे कदम-कदम पर अपनी

जाति विशेष के चलते कठिनायियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए वह बेहद सतर्कता और अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए निरंतर आगे बढ़ती हुई अपनी छवि को बेहतर बनाने की दिशा में कामयाब होंगी।

यह सच है कि जब किसी व्यक्ति पर जुनून हावी होता है, तो उसे उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। इसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। यह जुनून किसी भी रूप में हो सकता है। जब इस जुनून को सकारात्मक और सृजनात्मक रूप दिया जाता है तो बेहतर परिणाम सामने आते हैं, और वहीं यदि यह जुनून किसी गलत दिशा की ओर मुड़ जाता है तो न केवल स्वयं व्यक्ति विशेष को बल्कि संपूर्ण समाज और देश को भी तबाह कर सकता है। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के सकारात्मक और सृजनात्मक जुनून का ही यह सुखद एवं ऐतिहासिक परिणाम था कि उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भारत के संविधान की रचना की, जिसके आधार पर देश अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में चल रहा है। यहां के सभी नागरिकों को समान अधिकारों एवं मान-सम्मान की बात करता है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात करता है। यह समता, बंधुता का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर एक सफल अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, विधिवेत्ता, दूरदृष्ट्य, गरीबों, मजदूरों, दलितों एवं महिलाओं के सच्चे हितैशी होने के चलते दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में उनकी गिनती होती है। यही कारण है कि उनकी विद्वता योग्यता, समर्पणभाव, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया। उनकी 125वीं जयंती पर उनके जन्म

दिवस को पूरे वर्ष दलितों, गैर-दलितों, राजनैतिक दलों, संगठनों ने भारत और भारत के बाहर भी मनाकर दलितों की काबिलियत को ही सलाम किया है।

आज देश में जिस प्रकार से अन्याय, शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न आदि की घटनाओं की संख्या में बढोत्तरी हो रही है, उससे देश और समाज का ही नुकसान हो रहा है। जो लोग इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त होते, उन्हें नहीं मालूम कि वे क्या कर रहे हैं। उनकी विवेकहीनता, पारिवारिक संस्कार, बेरोजगारी, शिक्षा, आसपास का वातावरण और यहां की घोर जातिवादी मानसिकता की जिम्मेदार है। सही रूप में देखा जाए तो धर्म की दृष्टि से एक जाति और दूसरी जाति में कहीं कोई अंतर नहीं है। प्राकृतिक संसाधन सभी के लिए उपलब्ध हैं। किसी जाति विशेष, अमीर-गरीब, गोरे-काले, शहरी या ग्रामीण के लिए अलग-अलग नहीं हैं। इनमें भेदभाव केवल दूषित मानसिकता से भरे लोग ही करते हैं। सूर्य या चन्द्रमा का प्रकाश सभी को बिना भेदभाव के मिलता है। सुगंध सभी को मंत्रमुग्ध करती हुई आगे बढ़ती है। इसी प्रकार ज्ञान को भी सीमित नहीं किया जाना चाहिए। इसका प्रसार सभी तक पहुंचना चाहिए इसको बीच में ही अपने स्वार्थ के चलते अपने हित में मोड़ने या बाधक बनने की प्रक्रिया को नष्ट करना चाहिए। इसका प्रसार सभी तक पहुंचना चाहिए। इसको बीच में ही अपने स्वार्थ के चलते अपने हित में मोड़े या बाधक बनने की प्रक्रिया को नष्ट करना चाहिए। ऐसा यहां सदियों उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ करते आ रहे हैं। इसी के चलते देश में घोर जातीय विषमता का बोलबाला आज तक स्पष्ट रूप से दिखाई

देता है। उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति से उसकी जाति, उसकी शिक्षा, उसके पहनावे, उसके खान-पान यहां तक कि रहने और चलने पर भी घोर आपत्ति करते रहे हैं। इसी के चलते देश में अन्याय, शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न दिखाई देता है। एक जाति की उपलब्धि की खुशी दूसरी जाति के लिए कष्ट का कारण बनती है। इसके चलते विरोध की भावना पनपती है। उससे छीनने या नष्ट करने का प्रयास किया जाता है और कभी-कभी तो स्थिति भयानक रूप धारण कर लेती है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के शासकों का दायित्व बनता था कि सभी के साथ समान न्याय करें। ऊंचा हो या नीचा, स्त्री हो या पुरुष, बाल हो या वृद्ध लेकिन उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ नहीं निभाया और न ही अपना कर्तव्य समझा। ऐसे विचित्र वातावरण में आम आदमी की मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक है। सरकारी योजनाओं का सही रूप में भलीभांति यदि पालन किया गया होता तो देश में बेरोजगारी, अन्याय, शोषण, अत्याचार आदि की घटनाओं को अंजाम देने वाले निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण में बेहतर योगदान दे सकते थे। उनकी प्रतिभा का भलीभांति आंकलन कर उन्हें पर्याप्त मौका और साधन उपलब्ध कराकर उनके गलत दिशा में लगने वाली ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा जा सकता था, लेकिन ऐसा करने से बार-बार अनदेखा किया जा रहा है। इसके लिए वे ही जिम्मेदार हैं, जो प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए सक्षम थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न कर अपनी सकारात्मक और सृजनात्मक ऊर्जा को अपने निजी स्वार्थ

और लालच के चक्कर में निरंतर गलत दिशा में खफाते चले आ रहे हैं। ऐसी बेहोशी और मदहोशी भली स्थिति में समाज की प्रतिभा का आंकलन और फिर उसको तराशने का कार्य करने की कल्पना कैसे की जा सकती है? हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खूबी होती है, लेकिन हम उसकी खूबी की अपेक्षा उसकी कमी को ही फोकस करने में अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं यदि वही ऊर्जा उसकी सकारात्मक सोच और प्रतिभा को कार्यरूप में परिवर्तित करने पर बल दिया जाए तो बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं, उचित ज्ञान, समय एवं धन प्रबंधन के बीच तालमेल स्थापित करने की आज नितांत आवश्यकता हैं। इसके लिए विशेषज्ञता हासिल व्यक्तियों को उचित अवसर देते हुए इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना जरूरी है। इसी के बल पर हम गांव, कस्बा, शहर और महानगर में उपलब्ध प्रतिभा को वैज्ञानिक सोच के साथ उचित अवसर और साधन सही समय पर उपलब्ध करा सकते हैं। यह हम ऐसा करने में अभी भी विलंब करते रहे तो हम सभी के लिए कदापि अच्छा नहीं होगा। हमें जुनून पैदा करने वालों और जुनून लिए हुए लोगों बीच तालमेल स्थापित करना होगा। प्रतिभाओं को पैनी नजर से देखने, समझने, उचित मार्गदर्शन, साधन और सुविधा देकर आगे लाने वालों की है। हम इस बात को बार-बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि यही वह माध्यम है, जिसके बल पर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। मानव संसाधन का बेहतर सदुपयोग कर सकते हैं और बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के भारत के नवनिर्माण की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं।

– सम्यक भारत से साभार

बेहद पोंगापंथी और जातिवादी हैं प्रवासी भारतीय

आम धारणा है कि एक भारतीय विदेश की सरजमीन पर पैर रखते ही जेंटलमैन बन जाता है। वह सभ्यता के नए मूल्यों से परिचित होता है, अपने देश की तमाम रूढ़ियों से नाता तोड़ लेता है और सही मायने में एक आधुनिक व्यक्ति बन जाता है। यह बात एक हद तक ही सही है। कुछ लोगों में भले ही परिवर्तन आ जाता हो पर एक बड़े हिस्से पर शायद उल्टा ही असर होता है। भारत के बाहर जहां-जहां भारतीय बसे हैं, वहां उन्होंने न केवल जाति आधारित संगठनों, संस्थाओं की स्थापना की है बल्कि वहां भी वे निम्न कही जानेवाली जातियों के साथ खुल्लमखुल्ला भेदभाव करने में संकोच नहीं करते। लेकिन उनके चरित्र के दोहरेपन का आलम यह है कि वे चाहते हैं कि ये बातें ढकी-छुपी रहें। वहां के लोग यह सब न जानें।

आजकल अमेरिका के एक बड़े राज्य कैलिफोर्निया की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन चल रहा है। यह एक रूटीन प्रोसेस है जिसके तहत सिलेबस में नए विषय या तथ्य शामिल किए जाते हैं। इस क्रम में वहां सिलेबस में हिंदुओं के बारे में भी कुछ सूचनाएं शामिल की जा रही हैं। लेकिन इस पर विवाद हो गया है कि

जानकारियों को किस रूप में रखा जाए। भारतीयों का एक तबका चाहता है कि प्राचीन तथ्यों को नए सिरे से लिखा जाए और हिंदू समाज में मौजूद वर्ण व्यवस्था या छुआछूत की बात को साफ गोल कर दिया जाए। अमेरिका में रह रही दलित ऐक्टिविस्ट थेनमोझि सुंदरराजन ने पिछले दिनों ‘द हफिंग्टन पोस्ट’ में इस संबंध में एक लेख लिखा है जिसके मुताबिक प्रवासी भारतीयों के एक हिस्से में सक्रिय ‘धर्म सिविलाइजेशन फाउंडेशन’ की तरफ से दलील दी जा रही है कि हिंदुओं में जाति एवं पुरुष सत्ता का जिक्र किया जाएगा तो इससे हिंदू बच्चे ‘हीन भावना’ से ग्रस्त हो जाएंगे। यह उनकी ‘प्रताड़ना’ का सबब बन सकता है, लिहाजा इस उल्लेख को ढाल दिया जाए।

सुंदरराजन बताती हैं कि ऊपरी तौर पर आकर्षक लगने वाली यह दलील सच्चाई पर पर्दा डालने जैसी है क्योंकि वही तर्क नस्लवाद के संदर्भ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किताबों से उसकी चर्चा भी गायब की जा सकती है। लेकिन इन कोशिशों का विरोध भी हो रहा है। विभिन्न धर्मों व नस्लों से जुड़े संगठनों ने एकजुट होकर पाठ्यपुस्तकों में ऐसे हेरफेर की



कुवैत में दीवाली: काश, सभी एनआरआई मिल कर मनाते अपने त्यौहार

मुहिम पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि दक्षिण एशिया के इस हिस्से में जातिगत और धार्मिक असहिष्णुता या संस्थागत भेदभाव के प्रसंग को गायब करना न सिर्फ इतिहास को नकारने जैसा है बल्कि यह गैर लोकतांत्रिक भी है।

वैसे यह पहली दफा नहीं है जब कैलिफोर्निया की पाठ्यपुस्तकों की पुनर्रचना सुर्खियों में आई है। एक दशक पहले सिलेबस में बदलाव के मौके पर हिंदू धर्म को लेकर एक ऐसी आदर्शकृत छवि किताबों में पेश की गई, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। ब्रिटेन में भी भारतीयों के एक समूह का व्यवहार ऐसा ही है। वहां जातिगत भेदभाव दूर करने के लिए कानून में प्रावधान करने पड़े। ब्रिटेन में

जातिगत भेदभाव को ‘इक्वलिटी ऐक्ट’ के तहत गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है। पिछले साल वहां एक एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल ने भारतीय मूल की एक पूर्व घरेलू कामगार को, जो दलित ईसाई थी, एक लाख अस्सी हजार पाउंड का मुआवजा दिलाया। वह जिस परिवार में काम करती थी, वहां उसके साथ जाति और धर्म, दोनों ही आधारों पर भेदभाव होता था।

कुछ समय पहले मलेशिया में भारतीय मूल के निवासियों की गिरफ्तारी का मसला सुर्खियों में आया था। बताया गया कि हिन्द्वाफ नामक संगठन के कार्यकर्ता इस बात से नाराज थे कि मलेशिया के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाने वाला एक उपन्यास कथित तौर पर

भारत की छवि ‘खराब’ करता है। आखिर उपन्यास में ऐसी क्या बात लिखी थी, जिससे वहां रह रहे भारतवंशियों को अपनी मातृभूमि की बदनामी की चिंता सताने लगी? दरअसल उपन्यास में एक ऐसे शख्स की कहानी कही गई है जो तमिलनाडु से मलेशिया में किस्मत आजमाने आया है और यह देख कर हैरान होता है कि अपनी मातृभूमि पर उसका जिन जातीय अत्याचारों से सामना होता था, उसका नामोनिशान तक यहां नहीं है।

पिछले दिनों यह खबर आई कि दक्षिण एशिया के मुल्कों से ब्रिटेन में आकर बसे लोग अपनी संतानों, खासकर बेटियों की जबरन शादी करते हैं और अगर उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो ‘ऑनर किलिंग’ तक पर उतर आते हैं। यह कैसी विडंबना है कि जो संघर्ष दलितों को भारत में करना पड़ता है, वही उन्हें विदेशों में भी करना पड़ रहा है। आज की तारीख में अमेरिका और ब्रिटेन में कई दलित संगठन सक्रिय हैं, जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। सोचा जा सकता है कि इससे भारत की क्या छवि बनती होगी?

<http://blogs.navbharattimes.indiatimes.com/nbteditpage/number-of-emigrant-indians-are-fundamentalist-and-racist/kj.ml>

महाराष्ट्र में अब ६,५०० लोगों की बौद्ध धर्म में घर वापसी

महाराष्ट्र के सामाजिक संगठन सत्यशोधक ओबीसी परिषद ने कहा है कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े एक हजार से ज्यादा परिवारों को अगले साल की शुरुआत में बौद्ध धर्म में शामिल कराएगा। परिषद ने इस मुहिम को घर वापसी या होमकमिंग का नाम दिया है, जो विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के उस कार्यक्रम की तरह है, जिसमें मुस्लिमों का धर्मांतरण कर उन्हें हिंदू धर्म में लाने पर जोर दिया जा रहा है। परिषद ने दावा किया है कि सैकड़ों मराठा और कुछ ब्राह्मण परिवारों ने इस धर्मांतरण में हिस्सा लेने में रजामंदी जताई है, जिससे कुल लोगों की संख्या बढ़कर करीब 6,500 पहुंच गई है। हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फेसबुक पेज को लाइक करें।

सत्यशोधक ओबीसी परिषद के प्रेजिडेंट हनुमंत उप्रे ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया, ‘हम 14 अक्टूबर 2011 से इस कैंपेन पर काम कर रहे हैं। आज हमारी लिस्ट में 1,677 परिवार ऐसे हैं, जो बौद्ध धर्म अपनाने को तैयार हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की अलग-अलग जातियों से लेकर मराठा और ब्राह्मण तक शामिल हैं।’ महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता माधव भंडारी ने कहा कि पार्टी ऐसे किसी धर्मांतरण का विरोध नहीं करेगी, क्योंकि वह बौद्ध धर्म को भारतीय धर्म का हिस्सा मानती है। उन्होंने कहा, ‘अगर धमकी या लव जिहाद जैसी चीजों के जरिए धर्मांतरण होता है तो



हम इसका विरोध करेंगे।’

सत्ताधारी बीजेपी की साइंसेदार शिव सेना ने भी कहा है कि वह बलपूर्वक या लालच के जरिए किए जाने वाले किसी भी तरह के धर्मांतरण का विरोध करेगी। शिव सेना के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने कहा है, ‘हमने इस घटनाक्रम के बारे में सुना जरूर है, लेकिन हमारे पास इस बात का ब्यौरा नहीं है कि इसे कौन चला रहा है। अगर लोगों को प्रलोभन दिए जाने या डराए जाने के संकेत मिलते हैं तो हम यह सब नहीं होने देंगे।’

परिषद ने दावा किया कि अहमदनगर जिले में रहने वाले 50 से ज्यादा ईसाई, तीन मुस्लिम और तीन ब्राह्मण परिवार बौद्ध धर्म अपनाने के लिए तैयार हैं। उप्रे ने कहा कि परिषद

ने ही इस प्रोग्राम को ओबीसी की घर वापसी नाम दिया था, क्योंकि इसका मानना है कि पिछड़े वर्ग से जुड़े सभी लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं। उन्होंने कहा, ‘हम लगातार यह मांग कर रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े

लोगों को उनके अधिकार दिए जाएं।

वह हिंदू धर्म की परंपराओं का लगातार अनुसरण कर रहे हैं, जबकि धार्मिक नेताओं ने उन्हें कभी भी पूरे दिल से स्वीकार नहीं किया है।’ उप्रे ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाने वाला आरक्षण धीरे-धीरे घट रहा है, क्योंकि मराठा ओबीसी कम्युनिटीज में अतिक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिषद ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है और कोर्ट में केस भी लड़े हैं।

<http://m.navbharattimes.indiatimes.com/state/maharashtra/other-cities/satyashodhak-obc-parishad-plans-to-convert-a-thousand-families-to-buddhism-in-maharashtra/articleshow/45707048.cms>



पाठकों से अपील

‘वॉयस ऑफ बुद्धा’ के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा ‘जस्टिस पब्लिकेशंस’ के नाम से टी-22, अतुल ग्वाव रोड, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क ‘जस्टिस पब्लिकेशंस’ के खाता संख्या 0636000102165381 IFSC Code : PUB0013100 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया ‘वॉयस ऑफ बुद्धा’ के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास ‘वॉयस ऑफ बुद्धा’ नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए
एक वर्ष : 150 रुपए

परिसंघ की सदस्यता का विवरण भेजें

बार-बार आग्रह करने के बाद भी अभी तक अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की जो सदस्यता की रसीदें जारी की गयी थी, वापिस नहीं आ सकी हैं। परिसंघ के प्रदेश, जिला, ब्लाक इकाइयों के पदाधिकारियों व शुभचिंतकों, जिनके पास सदस्यता की रसीदें हैं, वे नाम, मोबाइल नं., जिला एवं प्रदेश लिखकर नीचे लिखे प्रारूप में अतिशीघ्र parisangh1997@gmail.com पर ईमेल करें।

सदस्य का नाम	मोबाइल नं.	जिला	प्रदेश
- डॉ० उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष			

डॉ० उदित राज के नेतृत्व में परिसंघ के आंदोलन की उपलब्धियां और संक्षिप्त परिचय

“इन्कम टैक्स कमिश्नर का पद छोड़कर आया हूं, दूसरी आजादी की लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता हूं। जब तक समाज के लोग दान-बलिदान न दें। जो सहयोग मिल रहा है वह निराशाजनक है। समझ में नहीं आता कि कैसे इस समाज का उद्धार होगा?”

**निजी क्षेत्र में आरक्षण एक स्थायी अधिकार की मांग है, यह सत्ता प्राप्ति से कम महत्वपूर्ण नहीं है ।
सांस्कृतिक चेतना एवं बौद्धमय के बिना मान-सम्मान एवं आर्थिक बराबरी नहीं मिल सकती ।
न्यायपालिका एवं सेना में आरक्षण और आरक्षण कानून बने । व्यापार करने वाला राज करेगा ।**



अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना 1997 में डॉ. उदित राज के नेतृत्व में की गयी। तभी से दलितों व आदिवासियों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्षरत है। सामाजिक आंदोलनों की अपनी सीमाएं होती हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए डॉ0 उदित राज जी ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। पहले अपनी राजनैतिक पार्टी बनाई लेकिन संसाधनों की कमी और समाज से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण सफलता नहीं मिली तो 2014 के लोक सभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर डॉ0 उदित राज लोक सभा में पहुंचे। वहां पर जब भी अवसर मिला उन्होंने दलितों, आदिवासियों एवं गरीबों से संबंधित मुद्दे उठाए। उन्होंने लोक सभा में पदोन्नति में आरक्षण, एक राज्य से बने जाति प्रमाण-पत्रों की सभी राज्यों में मान्यता, एस.सी.पी., टी.एस.पी., जामिया मिलिया इस्लामिया (अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय) में आरक्षण की अवहेलना, लघु एवं मध्यम उद्योगों में दलितों की भागीदारी, अजा/जजा को मिलने वाली छात्रवृत्ति का मुद्दा, आई.आई.टी.व एन.आई.टी. जैसे संस्थानों में आरक्षण की अहेलना व दलित छात्रों के साथ भेदभाव, एअरइंडिया में पॉयलटों की भर्ती में भेदभाव आदि से संबंधित मुद्दे उठा चुके हैं।

उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु प्राइवेट मेंबर बिल संसद में पेश किया है। इसके अलावा अजा/जजा के छात्रों को निःशुल्क छात्रावास की सुविधा, युवकों को अनिवार्य रूप से रोजगार मुहैया कराने आदि से संबंधित बिल भी लोक सभा में पेश किया है।

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ द्वारा डॉ0 उदित राज के नेतृत्व में चलाए जा रहे आंदोलन की उपलब्धियां एवं संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है।

जब 1997 में क्रमशः पांच आरक्षण विरोधी आदेश 30 जनवरी, 2 जुलाई, 22 जुलाई, 13 अगस्त एवं 29 अगस्त को जारी हुए तब इन्हें वापिस कराने के लिए अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना हुई। इसके बैनर तले पहली रैली 26 नवम्बर, 1997 को, दूसरी रैली 16 नवंबर, 1998 को, तीसरी 13 दिसम्बर, 1999 को एवं चौथी 11 दिसम्बर, 2000 को दिल्ली में हुई। इस रैली से पूरे देश में आंदोलन की लहर पैदा हुई और सरकार भी झुकी।

परिसंघ के इस प्रभावी आंदोलन के कारण आरक्षण विरोधी आदेश वापिस हो गए। इस तरह से सरकारी सेवाओं में आरक्षण के नुकसान को तो बचा लिया गया लेकिन दूसरी तरफ निजीकरण एवं उदारीकरण के कारण यह समाप्त होने लगा। सन् 2000 के आसपास केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों में लगभग 40 लाख दलित एवं आदिवासी कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत थे लेकिन अब वह संख्या घटकर लगभग 27 लाख हो गयी है।

अब निजी क्षेत्र में बिना आरक्षण के समाज की भागीदारी बरकरार नहीं रह सकेगी। जितना उत्थान सरकारी नौकरी में आरक्षण से हुआ, उतना किसी और योजना से नहीं। लोक सभा में आरक्षण के जरिए 122 सांसद बनते हैं अर्थात् 122 परिवार का उत्थान। देश में 28 राज्य हैं, जिनमें कुल 4109 विधायक चुनकर आते हैं। कोटे के अनुपात में लगभग 900 विधायक बनेंगे अर्थात् इतने ही परिवारों का भला। वर्तमान में लगभग 27 लाख कर्मचारी-अधिकारी सरकारी सेवा में हैं, अतः इतने परिवारों को मान-सम्मान एवं आर्थिक तरक्की। अब ज्यादातर नौकरियां निजी क्षेत्र में सृजित हो रही हैं, इसलिए इस नए संघर्ष का नाम दूसरी आजादी की लड़ाई देना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दलित-आदिवासी जब निजी क्षेत्र में नौकरी के माध्यम से घुसेंगे तो उन्हें व्यापार करने का तरीका भी मालूम होगा। यह सच्चाई है कि जो व्यापार करेगा वही राज करेगा। हमारा इतिहास इतना संघर्षशील एवं परिणाम दायक है कि शायद दूसरा कोई आंदोलन मुकाबले में है ही नहीं।

81वें संवैधानिक संशोधन के कारण संविधान में नई धारा 16 (4बी) जुड़ी जिससे रिक्त स्थानों (बैकलॉग पोस्ट) पर फिर से भर्ती शुरू हुई। इस 29 अगस्त 1997 के आदेश के अनुसार बैकलॉग पदों पर भर्ती इसलिए नहीं की जा सकती थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण द्वारा भर्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। इससे लाखों लोगों को लाभ पहुंचा और बेरोजगारों को भी नौकरियां मिलीं। यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह लड़ाई केवल दलित कर्मचारियों के लिए ही थी। 82वें संवैधानिक संशोधन के कारण संविधान की धारा 335 में आवश्यक परिवर्तन किया गया, जिससे 22 जुलाई 1997 का आरक्षण विरोधी आदेश वापिस हुआ। इस आदेश के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में मूल्यांकन में जो छूट मिलती थी, वापिस हो गयी थी। उदाहरणार्थ इसके पहले आयकर विभाग में दलित निरीक्षक आयकर अधिकारी परीक्षा आसानी से पास करते थे और उच्च पद पर प्रमोशन के लिए सामान्य वर्ग से अधिक कतार में लग जाया करते थे। जब तक यह आदेश निरस्त नहीं हुआ, विभागों में खोजना पड़ता था कि कितने दलित कर्म पदोन्नति के लिए परीक्षा पास कर चुके हैं। 85वां संवैधानिक संशोधन इसलिए किया गया कि 30 जनवरी 1997 के आरक्षण विरोधी आदेश ने दलित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वरिष्ठता के लाभ से वंचित कर दिया और उससे जुड़े अन्य फायदों को भी। हजारों की संख्या में रेल विभाग में कर्मचारियों की पदावनति होने लगी। हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों में भी हाहाकार मच गया। जहां मनुवादी नौकरशाही हावी है और दलित आंदोलन कमजोर है, वहां को छोड़कर शेष स्थानों पर वरिष्ठता का लाभ पुनः मिलना शुरू हो गया। इसके अतिरिक्त हमारे ही आंदोलन के प्रयास से महाराष्ट्र और जम्मू एवं

कश्मीर में आरक्षण कानून बना।

दो आरक्षण विरोधी आदेश अभी भी वापिस होने हैं। 2 जुलाई 1997 में पद पर आधारित नए रोस्टर प्रणाली को लागू किया गया। इसके अनुसार यह कहा गया कि दलित कर्मियों की उसी स्थान पर नियुक्ति या प्रमोशन होगा, जो आरक्षित बिन्दु (रोस्टर प्वाइंट) इनके हैं। पुराना रोस्टर 40 प्वाइंट का था, जिसमें प्रथम बिन्दु पर दलित और चौथे बिन्दु पर आदिवासी की भर्ती की जाती थी। इसे हटाकर नए रोस्टर में सातवें और 14वें बिन्दु पर दलितों की भर्ती की जाएगी, इस तरह से यदि किसी विभाग में पांच या छः पद हैं, तो उसमें एक भी दलित की भर्ती नहीं होगी, अगर 13 भर्तियां हैं, तो मात्र एक दलित की भर्ती हो जाएगी।

मेरी बात-चीत कई वरिष्ठ अधिकारियों से हुई और यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें पता ही नहीं है कि 77वां संवैधानिक संशोधन यदि लागू हो जाए तो उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा। 16 नवम्बर 1992 को मंडल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण दलितों को नहीं मिलना चाहिए। इस विसंगति को दूर करने के लिए 77वां संवैधानिक संशोधन जून 1995 में किया गया। संशोधन की भाषा स्पष्ट रूप से कहती है कि पदोन्नति में आरक्षण प्रत्येक पद और स्तर पर दिया जाना चाहिए। 13 अगस्त 1997 को जब कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया, तो उसमें कहा गया कि वर्तमान जैसा ही पदोन्नति में आरक्षण जारी रहेगा। अतः पदोन्नति में आरक्षण निचले स्तर तक ही मिलेगा, जैसा पहले था। संशोधन को यदि सही रूप से लागू किया जाए तो वरिष्ठ अधिकारी जैसे आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.आर.एस., डॉक्टर, इंजीनियर आदि जल्दी पदोन्नति पाते हुए अपने-अपने विभागों में टॉप पदों पर पहुंच जाएंगे, जैसे विभागाध्यक्ष, सचिव भारत सरकार, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन या सदस्य आदि। जैसा ऊपर मैंने बताया कि अधिकारियों को यह पता भी नहीं है। वास्तव में मूल संघर्ष में श्रेणी तृतीय एवं चतुर्थ के ही कर्मचारी ज्यादा आगे रहते हैं, जिसका लाभ समाज एवं अन्य श्रेणी के कर्मचारी उठाते हैं।

इन संवैधानिक संशोधनों के विरुद्ध परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी सामान्य वर्ग के संगठनों एवं नेताओं को उकसाया, ताकि वे अधिक से अधिक संख्या में तीनों संशोधनों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकें। मुझे उस समय आश्चर्य हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, तो देखा कि सामान्य वर्ग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की ओर से सैकड़ों याचिकाएं दाखिल की गई थी और बड़े-बड़े वकील उनकी ओर से पैरवी कर रहे थे। दूसरी तरफ केवल हम ही पैरवी करने वाले थे, तो अफसोस हुआ कि दलित कर्मचारी कितने स्वार्थी हैं। चेतन और अचेतन अवस्था में ये सोचते हैं कि कोई न कोई इनके लिए

संघर्ष कर ही रहा है, तो उन्हें आगे आने की क्या जरूरत है? इस तरह से लगभग सभी सोचने लगते हैं, परिणाम यह होता है कि कोई आगे नहीं आ पाता। दूसरा, इनमें गलतफहमी और अहंकार इतना है कि विभाग में अम्बेडकर जयंती मनाने या अन्य छोटे-मोटे कार्य करने से ही ये मान लेते हैं कि बड़ा काम कर दिया और इनकी आदत बकवास करने की तो है ही। कभी नेताओं की आलोचना करेंगे, तो कभी हमारी।

4 नवंबर, 2001 को परिसंघ के ही बैनर तले लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इरादा यह था कि दस लाख लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर एक महान सांस्कृतिक परिवर्तन का उद्घोष करेंगे। उस समय की सरकार ने न केवल रामलीला मैदान की अनुमति को रद्द किया बल्कि पुलिस बल का प्रयोग करके दीक्षा में भाग लेने वालों को डराया-धमकाया। मान-सम्मान की लड़ाई कहने से ही पूरी नहीं होगी जब तक कि सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा लोगों के विचार न बदले जाएं। वैचारिक परिवर्तन का बड़ा काम हमारे द्वारा ही हुआ और जिन्होंने मान-सम्मान के संघर्ष के लिए नारा दिया। और लक्ष्यों कर्मचारियों-अधिकारियों का तन, मन और धन से समर्थन हासिल किया, उन्होंने बेवकूफ बनाने के सिवाय कुछ नहीं किया। लोग तो विचारों से गुलाम होते हैं। गुलाम मानसिकता बिना विचार बदले नहीं मिटाया जा सकता।

झुजूर का मामला हो या अन्य उत्पीड़न के मामले उस पर हम ही लड़ते हैं। क्या किसी ने कभी सुप्रीम कोर्ट को घेरा है? इस साहसिक कार्य को हमने ही 10 अगस्त, 1998 को किया। हमारी आलोचना होती है कि हमने राजनैतिक पार्टी बना ली। अगर बनाया है तो परिसंघ के मुद्दों के समर्थन के लिए ही। कुछ बात राजनैतिक दल से संभव है तो कुछ सामाजिक मंच से। बनिया के पास राजनैतिक सत्ता नहीं है, फिर भी उसका वर्चस्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसका दबदबा आर्थिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में बरकरार है। एक दशक पहले तक तो उम्मीद थी कि सही एवं अम्बेडकरवादी सोच के कारण आंदोलन सही दिशा में जा रहा है, लेकिन अब वह तेजी से गिर रहा है। गिरने के पीछे सबसे बड़ा कारण दलितों में उपजातिवाद का पैदा होना है। एक तरफ जाति के आधार पर संगठन खड़ा करते हैं तो दूसरी तरफ अपने आपको समतावादी एवं अम्बेडकरवादी कहते हैं। इस जहर को फैलाने का काम दलित नेता भी कर रहे हैं। भविष्य अंधकार में है, कोशिश की जा रही है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लेकर जो उपलब्धि हुई है, उसी को बरकरार बना सकें।

निजी क्षेत्र में यदि आरक्षण नहीं मिलता, तो समझो जो भी तरक्की और प्रतिष्ठा अब तक मिली वह भी लुट जाएगी। राजनीति एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से ही दलितों ने सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। जहां आरक्षण नहीं है जैसे - मीडिया, उद्योग, कला एवं

संस्कृति, उच्च शिक्षा, उच्च न्यायपालिका, आयात-निर्यात, हाई-टेक आदि में आज भी दलितों ने कोई तरक्की नहीं की। अमेरिका में निजी क्षेत्र में आरक्षण अश्वेतों एवं मूलनिवासियों को मिल रहा है। वहां पर सरकार ने इनसे वस्तुएं एवं उत्पाद खरीदकर इन्हें उद्योगपति एवं व्यवसायी बना दिया है। इस अधिकार को लेने के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। सत्ता में व्यक्ति आता और जाता रहता है, जो अस्थायी है। निजीकरण और भूमण्डलीकरण की वजह से शिक्षा, नौकरी और धन-दौलत सब निजी हाथों में चला गया। हजारों अरबपति पैदा हो गए हैं। हर रोज अरबपति एवं खरबपति पैदा हो रहे हैं और उन्होंने अपने कालेधन की ताकत से राजनीति को भी नियंत्रित कर लिया है। बड़े-बड़े माल, मंहगी गाड़ियां एवं मकान और लाखों हजार करोड़ का व्यापार आदि सभी के मालिक तथाकथित स्वर्ण हो गए हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को देखते हैं तो लगता ही नहीं कि दलितों एवं पिछड़ों की भागीदारी थोड़ी भी हो। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे यह हमारा देश ही न हो। क्योंकि आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक सत्ता पर इन्हीं का पूरा कब्जा हो गया है। अब से कुछ साल पहले स्थिति कम से कम कुछ बेहतर थी, जब जमींदार और उसके खेत पर काम करने वाले मजदूर के बच्चे एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। निजीकरण से सुविधाओं एवं अधिकारों में बड़ा फासला हो गया है।

जब देश का राष्ट्रपति दलित नहीं था तब चर्चा होती थी कि एक बार दलित राष्ट्रपति हो जाए तो संभव है कि कुछ परिवर्तन हो। ऐसी ही बात मुख्य न्यायाधीश के बारे में कही जाती थी। अंत में दलित मुख्य न्यायाधीश हुए भी तो भी खास परिवर्तन नहीं हुआ। सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री, सुश्री मायावती चार बार बन चुकी हैं तो क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण मिल सका? यदि कोई दलित प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा स्थायी अधिकार प्राप्त ही हो जाए। हो सकता है, अन्यो से भी कम काम कर सकें, क्योंकि सत्ता में बने रहने की तमाम मजबूरियां होती हैं। जब इसके लिए देश भर में आंदोलन खड़ा करेंगे तो हर पार्टियां वोट की लालच में झुकेंगी और एक दिन यह अधिकार मिलकर रहेगा। मान-सम्मान और राजसत्ता प्राप्ति के नारे ने खूब आकर्षण पैदा किया और बड़े सपने दिखाए। लोगों ने खूब कुर्बानियां दीं। हो सकता है कि हमारा नारा बड़ा सपना दिखाने वाला न हो लेकिन हमारी लड़ाई राजनैतिक सत्ता हासिल करने से कम की नहीं है। सहारा कंपनी में लगभग 9 लाख कर्मचारी हैं यदि यहां निजी क्षेत्र में आरक्षण होता है तो लाखों दलित-आदिवासी परिवारों को रोजगार मिलेगा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम कितने बड़े उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

डॉ0 अम्बेडकर 26, अलीपुर रोड, दिल्ली में रहे। यहीं पर रहते हुए 'बुद्ध और उनका धर्म' ग्रंथ की रचना की व तमाम संघर्ष किया और यहीं पर उनका शेष पृष्ठ 5 पर....

नए भविष्य की झलक

1858 में बॉम्बे प्रेसीडेंसी की ब्रिटिश सरकार ने भारी विरोध के बावजूद सभी सरकारी स्कूलों के दरवाजे पहली बार दलितों के लिए खोले थे। उस समय बड़ौदा, कोल्हापुर,त्रावणकोर जैसी रियासतें इसी दिशा में कदम उठा रहे थे।

1858 में बॉम्बे प्रेसीडेंसी की ब्रिटिश सरकार ने भारी विरोध के बावजूद सभी सरकारी स्कूलों के दरवाजे पहली बार दलितों के लिए खोले थे। उस समय बड़ौदा, कोल्हापुर,त्रावणकोर जैसी रियासतें और सवित्रीबाई फुले, नारायण गुरु जैसे समाज सुधारक भी इसी दिशा में कदम उठा रहे थे। इसमें शिक्षा संस्थानों में दलितों के लिए दाखिला खोलना, छात्रवृत्तियां आरंभ करना और अन्य कार्य शामिल थे। इन नई संभावनाओं से लाभान्वित होने वालों में से एक नाम भीमराव रामजी अंबेडकर का था, जिन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स तक का सफ़र तय किया। वह अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय बने और आगे चलकर आधुनिक भारत के निर्माता कहलाए। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलित वर्ग के लिए मुसलमानों की तरह पृथक निर्वाचन का प्रावधान जारी कर दिया। भारत के राजनीतिक भविष्य के लिए इसके दूरगामी परिणाम को देखते हुए इसी वर्ष राजा-मुंजे पैक्ट हुआ जिसमें दलितों के

लिए पृथक निर्वाचन के बजाय आरक्षित सीटों पर सहमति बनी थी। डॉ. मुंजे हिंदू महासभा के नेता थे जो कांग्रेस की राजनीति से किनारा करके आए थे। उन दिनों एमसी राजा दलित नायक थे जो पेरियार की द्रविडियन राजनीति का दलित विरोधी चरित्र देख कर जस्टिस पार्टी छोड़ कर आए थे। वह ब्रिटिश-इंडिया की इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउन्सिल के पहले दलित सदस्य भी थे। इसके तुरंत बाद ही प्रसिद्ध पूना पैक्ट हुआ जिसे गांधी-अंबेडकर पैक्ट भी कहा जाता है। हालांकि इस पैक्ट पर गांधी के हस्ताक्षर नहीं हैं। इस समझौते का दूसरा पक्ष वह था जिसे आज हिंदू दक्षिणपंथ कहा जाता है। इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, और पूंजीवादी विचार के समर्थक सी रजगोपालचारी तथा वालचंद हीराचंद जैसे बड़े उद्योगपति शामिल थे। पूना पैक्ट ने न सिर्फ दलितों के लिए आरक्षण के प्रावधान को स्वीकार किया, बल्कि सरकारी नौकरियों में भी दलितों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का प्रण लिया। पूना पैक्ट वस्तुतः एक सामाजिक अनुबंध जैसा जिसमें उत्तर-औपनिवेशिक राज्य की सामाजिक नीति की दिशा तय की गई थी। इसे भारतीय गणराज्य का प्रथम मूलभूत दस्तावेज भी कहा जा सकता है। पूना पैक्ट के बिना दलितों को अधिकारिक तौर पर हिंदू समाज से पृथक गिना जाता और इसके चलते आबादी के आधार पर हुए बंटवारे के समय हिंदू आबादी का प्रतिशत काफी काम हो जाता और भारत का वर्तमान राजनीतिक नक्शा शायद कुछ और

होता। बंगाल में ऐसा ही हुआ। यहां पर कई हिस्से पाकिस्तान में इसलिए चले गए, क्योंकि उन इलाकों के दलितों को मुस्लिम लीग अपने साथ जोड़ने में सफल रही थी। इसी तरह की स्थिति पंजाब में बनी। यहां लाहौर समेत कई इलाके ईसाइयों के वोट के कारण ही पाकिस्तान का हिस्सा बने। स्वतंत्र भारत ने भी दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को कायम रखा और शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों का स्थान सुरक्षित किया। आजादी के बाद दलित उत्थान के लिए किए गए प्रयासों में आरक्षण ही सबसे सफल नीति रही है। आज समाज में जो सामाजिक गतिशीलता और परिवर्तन दिखता है उसका एक मुख्य कारण आरक्षण है, जिसने संभवतः विश्व में सबसे बड़े मध्यवर्ग को इतने कम समय में निर्मित किया है। आज आरक्षण से लाभान्वित पीढ़ी के बच्चे बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी से इतर क्षेत्रों में जा रहे हैं और बिना आरक्षण के ही सफलता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनकी सफलता में भी आरक्षण नीति का योगदान है, क्योंकि उसी ने उनसे पहले की पीढ़ी को यह अवसर प्रदान किया कि वह अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक नया भविष्य दे सके। इसी नए भविष्य की झलक हाल में तब दिखी जब दलित जाति से आने वाली एक लड़की टीना डाबी ने विश्व की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संघ लोकसेवा आयोग में प्रथम प्रयास में ही शीर्ष स्थान हासिल किया और वह भी महज 22 साल की उम्र में। आम तौर यह कहा जाता है कि

आरक्षण से अक्षम लोगों का चयन होता है और उससे संस्थानों की दक्षता कम होती है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि आरक्षण से देश 'बर्बाद' हो रहा है। सच्चाई इससे कोसों दूर है। इसके कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं हैं कि आरक्षण से संस्थानों की काबिलियत कम हो रही है। 2010 में अश्विनी देशपांडे और अमेरिकी प्रोफेसर थॉमस विस्कोफ द्वारा रेलवे पर किए गए एक विस्तृत सर्वे में यह पाया गया था कि आरक्षण से संस्थागत दक्षता और काबिलियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सर्वे के नतीजे वर्ल्ड डेवलपमेंट जर्नल में भी प्रकाशित हुए थे। सर्वे के अनुसार आरक्षण रेलवे में उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने में सहायक बना। आरक्षण से मेरिट का नुकसान होने की अवधारणा इस पर आधारित है कि बिना आरक्षण के केवल मेरिट की बंदोलत ही चयन होता है। जातियों और भाई-भतीजावाद से भरे समाज में यह संभव नहीं है फिर भी कई लोग यह सब रोज देखकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि आरक्षण ने देश के एक बहुत बड़े तबके को समान अवसर देकर उसे मुख्यधारा में लाकर मेरिट का दायरा बढ़ाया है। आरक्षण का मुद्दा जटिल तब हुआ जब मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। इसके तहत तय पैमाने इस प्रकार के हैं कि कोई भी जाति इसमें शामिल होने का दावा कर सकती है, अगर वह सामाजिक रूप से पिछड़ी है। सामाजिक रूप से ताकतवर कई मंझली जातियों को इसके तहत

आरक्षण मिल रहा है। इसके कारण ही पटेल, जाट और इन जैसी अन्य जातियां यह सवाल कर रही हैं कि आखिर उन्हें आरक्षण से बाहर क्यों रखा गया है? चूंकि आरक्षण अब चुनावी वादों में बटने लगा है इसलिए स्थिति और जटिल एवं विस्फोटक होती जा रही है। अब जब आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है तब इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जिन जातियों को आरक्षण की सबसे अधिक आवश्यकता थी उन्होंने कभी भी इसके लिए सड़क पर उतर कर हिंसा नहीं की। उल्टे उनके आरक्षण के समर्थन में शेष जातियों के लोग खड़े हुए। आरक्षण की बढ़ती मांग का मुख्य कारण अवसरों की कमी है। अगर 1.25 अरब अबादी वाले देश में सिर्फ गिनती की नौकरियां होंगी तो फिर आरक्षण के विरोध और पक्ष में इन नौकरियों के लिए मारामारी तो होगी ही। यह भारत की सबसे बड़ी असफलता कही जाएगी कि आजादी के इतने दशकों बाद भी देश में सबके लिए गुणवत्ता वाले प्राथमिक स्कूल तक नहीं हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज की बात तो भूल ही जाइए। उम्मीद है कि देश के नीति-निर्माता इस तरफ ध्यान देंगे ताकि जैसी उपलब्धि टीना डाबी ने हासिल की वह अनोखी नहीं, बल्कि आम बात हो जाए।

(लेखक अभिनव प्रकाश, दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)
<http://www.jagran.com/editorial/apnibaat-glimpse-of-new-future-14016217.html>



डॉ० उदित राज के नेतृत्व में परिसंघ के आंदोलन का संक्षिप्त परिचय

पृष्ठ 5 का शेष....

6 दिसंबर, 1956 को परिनिर्वाण हुआ। बड़ी जद्दोजहद के बाद 2003 में भारत सरकार ने इसे खरीदा और राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, लेकिन वहां न कोई सेमिनार होता है और न ही अन्य तरह की गतिविधियां। डॉ. अम्बेडकर परिनिर्वाणभूमि सम्मान कार्यक्रम समिति बनाकर इसे गांधी समाधि के बराबर का दर्जा देने के लिए आंदोलन चलाया गया और सफलता मिली। गत् 14 अप्रैल को इस स्थल पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी स्वयं आए और उन्होंने घोषणा की 95 करोड़ रुपये की लागत से इसका सौंदर्यकरण किया जाएगा। अभी भी हमारी मांग है कि राजघाट की तर्ज पर ऐक्ट बनाकर इसका सुंदरीकरण किया जाए और इसके विस्तार के लिए आस-पास की भूमि को अधिगृहीत की जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त हमारा संघर्ष न्यायपालिका में आरक्षण, सफाई कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति, आरक्षण कानून बनवाकर 9वीं सूची में रखवाना, समान एवं अनिवार्य शिक्षा, समता मूलक समाज की स्थापना एवं राज्य सरकार की सेवाओं में 1950 के बाद आए दलितों को आरक्षण का लाभ

दिलवाना आदि, जारी रहेगा।

कहने और बोलने में कुछ लगता नहीं, लेकिन उपरोक्त अधिकारों को लेने के लिए कड़े संघर्ष करने पड़ेंगे। संगठन की शाखाएं ब्लॉकों और गांवों तक बनानी होंगी। सदस्यता अभियान युद्धस्तर पर चलाना पड़ेगा। मनुवादियों से कुछ तो सीखना चाहिए। अविवाहित और उच्च शिक्षा प्राप्त सैकड़ों लोग आर. एस.एस. के प्रचार में लगे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी - अधिकारी संघ परिवार के तमाम संगठनों को संभाल रहे हैं। नाम व प्रसिद्धि के लिए कभी कोई टकराव सुनने में नहीं आता।

हमने विशेषतौर से दिल्ली में कुछ कर्मचारियों की पहचान बनाई, तो उनका हाजमा ही खराब हो गया। समझने लगे कि बड़े नेता हो गए हैं। इस तरह से परिसंघ विरोधी गतिविधि में लिप्त होते हुए समाप्त हो गए। हमारे तमाम सेवानिवृत्त कर्मचारी-अधिकारी अहंकार या तुच्छ सोच के कारण न समाज से लाभ ले पाते हैं और न ही दे पाते हैं। शोषित समाज को तो और भी समर्पित होना चाहिए। जगह-जगह पर प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएं और ऐसे मिशनरी तैयार किए जाएं, जो समाज को बदलकर रख दें। आशावान होते हुए

उम्मीद की जा रही है कि परिसंघ को सैकड़ों एवं हजारों मिशनरी एवं समर्पित नेता व कार्यकर्ता मिलेंगे, जिससे एक नया समाज तैयार होगा।

राज्य स्तर पर सदस्यता फार्म छपे गए हैं, जिसे प्रदेश के नेताओं से प्राप्त किया जा सकता है, यदि असुविधा हो तो केन्द्रीय कार्यालय से मंगवाया जा सकता है। सदस्यता शुल्क एक वर्ष के लिए 100/- रुपये और आजीवन 1000/- रुपये रखी गयी है। सदस्यता शुल्क एवं चंदा सीधे परिसंघ के घाते में जमा किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्नवत् है -

Name of Beneficiary : All India Confederation of SC/ST Organisations
Name of Bank : State Bank of India
S a v i n g B a n k A c No.:30899921752
Branch Name : Chanderlok Building,1st Floor, Janpath, New Delhi
IFSC Code : SBIN0001639

बिना विचारधारा एवं सूचना के आंदोलन चलाना मुश्किल है।

वॉयस ऑफ बुद्धा का संपादन इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। 'वॉयस ऑफ बुद्धा' की वार्षिक सदस्यता 150 रुपये एवं पांच वर्ष के लिए 600 रुपये है। सदस्यता शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 (पंजाब नेशनल बैंक की शाखा जनपथ, नई दिल्ली- 110001) IFSC Code : PUNB0013100 में सीधे जमा कर

सकते हैं या बैंक ड्राफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम भेजें। इसकी सूचना या तो ईमेल द्वारा दें या दूरभाष पर। कृपया सदस्यता शुल्क मनीआर्डर के माध्यम से न भेजें।

-: निवेदक :- अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of '**Justice Publications**' at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National **Bank account no. 0636000102165381 IFSC Code : PUB0013100** branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

46th SHAHEEDI DIWAS OF BHAGAT AMAR NATH JI OBSERVED AT DODA - RESOLUTION TO HOLD STATE CONVENTION ON 12TH JUNE TO SAVE RESERVATION

A large gathering assembled at Doda under the aegis of All India Confederation of SC/ST Organizations Doda Unit at Sports Stadium, Doda the birthplace of Shaheed Bhagat Amar Nath, who sat on a fast until death at Karan Park, Jammu and attained martyrdom on 1st June 1970 after which the then Government of Jammu and Kashmir implemented provisions of reservation in Jammu and Kashmir, 20 years after such reservation was made applicable throughout the rest of India in 1950 by the Constitution. Dr. Udit Raj, Member of Parliament (Lok Sabha) and National Chairman, All India Confederation of SC/ST

progress we have made till date is due to efforts of people like Shaheed Ji, and now it is the duty of those who have benefited from reservation to save reservation now, so that such rights can percolate down to the last man remaining. He also said that being a Member of Parliament, he had raised the issues of rights not only in his Constituency, but also for SC/STs throughout India. He had also spoken in Parliament about issues of Jammu and Kashmir like total share of SC/ST reservation, injustice faced by OBCs due to non-implementation of Mandal Commission recommendations, issues of Gurjar Bakerwal, equal share in SCP/TSP etc. Dr. Udit Raj



**National Chairman, Dr. Udit Raj, MP,
State President of J & K Confederation R. K. Kalsotra with
other leaders and supporters of Confederation**

gathering that after returning to Delhi, he will again caution the State and Central Governments to restore reservation in promotion rights to Jammu and Kashmir employees.

Shri Inderjeet Megh apprised the gathering that mission of his Sabha was to help poor students of society by adopting them and distributing scholarships. They had great respect for Shaheed Bhagat Ji and assured the Confederation about his Sabha's entire support to save rights. R K Kalsotra congratulated the Chenab Valley people for organizing such Mega Shaheedidivas and said that their unity has definitely sent a strong signal to Govt. to bring the positive results for whole community & he hoped other district will follow the example set by them. He further said since 1997 Confederation is on path of struggle having so many

credits to its name recent among which was struggle which compelled the State Govt. to amend reservation in New Recruitment Policy. To get back reservation in promotion, timely scholarship to students, equal share in component plans, toto implementation of Mandal Commission Report, House for House less and for many other demands they have been struggling. To get back reservation in Promotion Mr. Kalsotra asked the people to assemble in Srinagar on 12th of June 2016 in large numbers to hold convention/protest. He asked all to join to save rights and it shall be real tribute to Shaheed Ji then.

District President Retd. DFO Amar Nath Bhagat appreciated the large gathering on its participation and assured that they will continue struggle by uniting each and every depressed

people. B L Bhardwaj State General Secretary while delivering his address appealed the gathering to participate on 12th June in large numbers at Srinagar to caution the Govt. to take back reservation in promotion which was their Constitutional right. Tarsem Garu, R R Bakolia, Vijay Kumar, Sabir Choudhry, Dina Nath, Hanley Kohli, Bishan Lal, Piar Chand Bhagat, Ashiq Watal, Parveen Jaryial, Ram Lal, Girdharilal, Kuldeep Kumar, Ram Sarn Bhagat, Gita ram, Om parkash bhagat, Suresh Bhagat, Baldev Singh, Santosh Kumar Bhagat, Manoj Kumar Bhagat, Surjeet Singh, Bhagat Bal krishn, Choudhry Mohd Haneef, Ashiq watal and Johan Mohd also spoke on the occasion and assured to follow the path of struggle shown by Shaheed Bhagat Sahib.



Organizations participated as the Chief Guest on the occasion along with Shri R K Kalsotra, State President All India Confederation of SC/ST Organizations. Shri Inderjeet Bhagat, veteran leader and National President, Megh Sabha Chandigarh was the guest of honor at the function. Leaders of the Confederation from Punjab, Chandigarh, Rajasthan, Haryana, Himachal Pradesh and Delhi along with representatives from all the districts of Jammu and Kashmir participated in the event.

also said that he already apprised the State and Central Governments about these issues such as snatching of reservation in promotion and for that Kalsotra Ji and Bharadwaj Ji were already in touch with him for that. He also said that he had engaged senior advocates with vast experience in the Nagaraj case, but until people come together and compel the State Government, there is little chance of success.

In 2001, the Confederation held a record gathering at Delhi after which the Atal Bihari Vajpayee Government passed three Constitutional Amendments, so Dr. Udit Raj requested people to support the Confederation and join their struggle. He also said that our voice should be one in the entire Government to pressurize the Government. He suggested to follow the path shown by the Jats, Patels and Gurjars who without any support from political leaders agitated and got reservation, whereas our communities are losing due to their dependence on political leaders, and due to their habit of demanding resignation of leaders, without doing anything themselves. He also said that we should become stronger socially to fight and save Constitutional rights. Dr. Udit Raj assured the

It was the first ever grand gathering of Dalits, tribals, downtrodden Muslims from Watal community as well as from OBC and RBA communities. Dr. Udit Raj, Shri RK Kalsotra and Shri Inderjeet Bhagat were received at Dak bungalow by thousands of people, who took out a rally towards sports stadium where the function was inaugurated by garlanding a portrait of Shaheed Bhagat Amar Nath Ji. While addressing the huge gathering, Dr. Udit Raj recalled Shaheed Bhagat Amar Nath Ji as an icon of society and the 2nd Ambedkar of India, and said that had he not made the supreme sacrifice, there would have not been any progress of society in Jammu and Kashmir. Elaborating further on this, Dr. Udit Raj said that whatever

मुंबई में परिसंघ की चिंतन बैठक संपन्न

मुंबई, 4 जून, 2016.

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की मुंबई इकाई की ओर से मुंबई विद्यापीठ में परिसंघ की चिंतन बैठक का आयोजन किया गया था। परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन, डॉ. उदित राज सांसद ने बैठक को संबोधित करते हुए मुंबई में परिसंघ के विस्तार के लिए अलग-अलग स्थानों में कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिसंघ की सदस्यता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में मुंबई में एक लाख लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाना चाहिए।



डॉ० उदित राज के साथ डॉ० संजय कांबले, संजय अधांगले, सुनील झोड़े, सिद्धार्थ कांबले, डॉ० जाधव आदि

डॉ० संजय कांबले ने आश्वासन दिया कि जल्द ही ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाकर राष्ट्रीय कार्यालय को सूचित किया जाएगा। उन्होंने मुंबई में परिसंघ के विस्तार और सदस्यता में आने वाली दिक्कतों का उल्लेख किया। इस अवसर पर परिसंघ के महाराष्ट्र सचिव, संजय अधांगले, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स फॉर अफरमेटिव ऐक्शन के चेयरमैन, सुनील झोड़े, सिद्धार्थ कांबले, डॉ० जाधव आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 19

● Issue 14

● Fortnightly

● Bi-lingual

● Total Pages 8

● 1 to 15 June, 2016

Relevance of Buddha in todays times

21st May is being celebrated as Buddha Purnima in honour of Sidharth Guatam Buddh who has given us a lot. When we talk about religion, it is impossible to not talk about the so called differences between men and women. Most religions, large or small, have considered men to be superior to women. Why was no woman the founder of a religion? This shows that society has been male centric for thousands of years. When Lord Buddha started spreading his political philosophy, power lay only with men. In Buddhism, sin and good are defined only by actions, and not by tradition or for any other reasons. The contributions of Buddhism towards women's liberalisation are perhaps unmatched by any other religion.

2500 years back, it was thought that one who had no sons could not attain moksha. Religious festivals, chants etc. could only be performed by the

male child. Women's role was limited to producing children and household works; women were burdened with household responsibilities to keep them busy. The thought was that if women were not kept busy, they might get up to some mischief. A woman's first duty was to take care of her husband. A woman could not attain moksha on her own, for that she had to be born in another life as a man. It was necessary for her to give birth to a male child, since otherwise neither the family would continue nor would religious requirements get fulfilled. Gautam Buddha considered this to be a fallacy and challenged people as to how women can be responsible for the sins and virtues of men, which gave a lot of confidence and relief to women. Due to the Buddhist movement, women got a chance to live independently, on their own terms. They could take care of their parents and families, as well as own

property. Indeed, there was a time when the kind of Kaushal was unhappy when a daughter was born to him. Gautam Buddha explained to him that some women are more intelligent than men, and their capacity to love and empathise is also much greater.

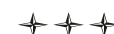
Gautam Buddha also spoke about his views on beauty. A beauty named Khema was the pride of the kingdom of Raja Bimbisar. She was also extremely proud of her beauty. One day she went to one of Gautam Buddha's sermons. The Buddha was an expert in humanities and could easily understand Khema's pride, due to which he said that humans always go from childhood to youth to old age. In old age, everyone needs support and can't even walk alone. Khema understood his message which made her a better human, and later she also became one of the biggest proponents of Buddhism. The story of Kisa Guatam is known

to almost everyone - she could conceive a child only after the greatest difficulties, which too she lost to an untimely death. When she had almost gone mad with grief, people told her that the Buddha had the power to bring life to the dead. Kisa Gautam went to the Buddha, and pleaded with him to make her child alive again. The Buddha asked her to bring a leaf from a house in which there has never been any death, so her child could live again. She searched and is unable to find any such house, due to which she realises that death is inevitable.

Within five years of the enlightenment of the Buddha, the Buddhist movement started gaining pace. Male and female monks both got the independence to preach about Buddhism, and both started visiting all parts of India as well as other countries to spread the message of Buddha. Sanghamitra, daughter of Emperor Ashok, went to Sri

Lanka, and for several years Buddhist monks were successful in spreading the message. However, later men started dominating the Buddhist movement and were successful in excluding women from their sphere. In China and Japan, female monks are still working and their independence and courage can be seen even today. Religion gives birth to both traditions and thoughts, which is why even today, in Burma, England, Colombia, China, Japan etc. women play active and equal roles in education, industry etc. Buddhism allows argument and constructive thought, and men's fates are decided only by their actions. In such a religion, women are not considered impure nor are they considered to be the source of sin. Due to this, it is natural that men and women are considered equal.

Dr. Udit Raj



It is not possible to inform everyone at an individual or organization level about messages and news neither is it possible for the office of the All India Confederation of SC/ST Organizations or the National Chairman to be personally apprised about every problem or issue. Society is changing, the country is changing and now it is time for you to change as well. If you are unable to change, then the mission and all our efforts will go in vain. Now easy, cheap technologies have become available, we should start using them for the benefit of our mission.

Multiple times we have asked you to share names, mobile numbers and email addresses of missionaries. Results have not been very good, but if everyone considers this their responsibility and starts working, then this process can be speeded up.

No organization can survive without financial support. If we have become officers and employees, is because of reservation? Our parents and grandparents had not got the benefits of reservation. This right was given by Dr. B R Ambedkar and we are enjoying its benefits. Some of us who are selfish or casteist can say that we have studied hard and become employees due to our own hard work. These people should be asked why their parents and grandparents could not study and become officers? This is an opportunity due to which all of this has become possible. Those who speak about their intelligence and hard work; they have done it only for their self interest, and have done nothing for society. Hence, the money and respect they have earned is due to Dr. Ambedkar, the opportunity they have been given and due to their birth in this society. Society has a right to share this money and respect. The fight for reservation in promotion and reservation in private sector is not easy; therefore, we are providing the account details of the All India Confederation of SC/ST Organizations for financial support. Please deposit your contribution in this account, and inform us through whatsapp or email.

Account details :

Name of Beneficiary :

All India Confederation of SC/ST Organisations

Name of Bank : State Bank of India

Saving Bank Ac No.:30899921752

Branch Name :

Chanderlok Building, 1st Floor, Janpath, New Delhi

IFSC Code : SBIN0001639

Contact details



parisnagh1997@gmail.com



97-17-046-047



Facebook www.facebook.com/parisangh.all.india.uditraj

Sumit Kumar 09868978306

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.

Website : www.uditraj.com

E-mail: parisangh1997@gmail.com

Computer typesetting by C. L. Maurya